

an>

Title: Need to implement Skill Development Programmers in Satna Parliamentary Constitution, Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): स्किल इंडिया अभियान के तहत दिनांक 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री जी ने 4 नई पहलों का उद्घाटन किया जिसमें राष्ट्रीय कौशल अभियान, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता योजना 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना। इन पहलों का उद्देश्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। इनमें से पीएमकेवीवाई स्किल इंडिया कार्यक्रम की रीढ़ है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सबसे प्रमुख योजना है। कौशल प्रमाणन की इस योजना का मकसद भारी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योगों के अनुकूल कौशल का प्रशिक्षण देना है ताकि उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिल सके। पहले ही सीख चुके या कौशल प्राप्त कर चुके लोगों का भी पूर्व प्रशिक्षण मान्यता कार्यक्रम के अंतर्गत आकलन और प्रमाणन किया जायेगा। इसमें समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम जोड़े जाते हैं। अभियान के दो वर्ष पूरे होने पर 100 जीएसटी प्रशिक्षण केंद्रों, 51 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों तथा 100 योग प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया गया। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण योजना बनकर उभरी है, जहाँ इससे पुनर्वास तथा रोजगार सृजन का दोहरा उद्देश्य पूरा होता है।

वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन 16 प्रतिशत बढ़ाया गया है। तीन प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, आजीविका के लिए कौशल संवर्धन एवं ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम तथा औद्योगिक मूल्य वर्धन हेतु कौशल विकास कार्यक्रम के अगले चरण का प्रस्ताव रखा गया है। अतः इनमें मध्य प्रदेश को विशेष रूप से मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना को शामिल किया जाए।